



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श०)

(सं० पटना 1016) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं० ०८/आरोप-०१-३०७/२०१४, सा०प्र०—१४५३०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

25 अक्टूबर 2016

श्री सुधांशु कुमार चौबे, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक—1089/०८, ८५८/११ तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायधाट, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुर्विनियोग के आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०—९८/२००८, दिनांक 25.11.2008 दर्ज हुआ। जिसमें ये प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये। एतदसंबंधी निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा (पत्रांक—१७ नि०गो०, दिनांक 23.01.2009) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक—४३४, दिनांक 09.02.2009 द्वारा श्री चौबे को निलंबित किया गया। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—१०८५, दिनांक 13.04.2009 द्वारा श्री चौबे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निमित आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। श्री चौबे ने अपने निलंबनादेश के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। संदर्भित सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०—१३८०५/०९ में दिनांक 04.11.2009 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक—५३५, दिनांक 18.01.2010 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री चौबे को निलंबन मुक्त कर दिया गया।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए श्री चौबे से स्पष्टीकरण माँगी गयी। इस क्रम में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया जिसपर संबंधित जिला पदाधिकारी मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक—११९९, दिनांक 12.04.2013 द्वारा यथा वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया तथा श्री चौबे के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया। उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक—८९३६, दिनांक 07.06.2013 द्वारा श्री चौबे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक—२३०९, दिनांक 19.11.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री चौबे के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तदुपरांत आरोपवार अनुशासनिक प्राधिकार के असहमति में निहित आरोपों की प्रमाणिकता को

स्पष्ट करते हुए विभागीय पत्रांक-9199, दिनांक 25.06.2015 द्वारा पर श्री चौबे से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री चौबे का स्पष्टीकरण (पत्रांक-978, दिनांक 08.07.2015) प्राप्त हुआ।

4. आरोप प्रपत्र 'क', संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौबे से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि काम के बदले अनाज योजना में मजदूरी के रूप में नगद एवं खाधान्न दिया जाना था परन्तु बिना खाधान्न दिये ही योजना कार्यान्वित करायी गयी। जो उक्त योजना के मूल उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल कृत्य था। मस्टर रौल एवं कार्य का तुलनात्मक सत्यापन किये बिना ही अभिकर्ता को भुगतान किया गया तथा इस पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। मस्टर रौल की सम्यक् रूप से जाँच नहीं की गयी। जिसके कारण मजदूरों के नाम की अनियमित प्रविष्टि हुई। मस्टर रौल एवं मापी पुस्त की जाँच प्रखंड कार्यालय के स्तर पर भी की जानी चाहिये थी। आरोपित पदाधिकारी ने योजना सं०-३५/२००५-०६ के कार्यान्वयन के क्रम में अभिकर्ता को अग्रिम प्रदान करने में लापरवाही बरती। संबंधित जिला पदाधिकारी ने भी उपर्युक्त आरोपों पर दिये गये अपने मंतव्य में यह प्रतिवेदित किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में श्री चौबे द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में गम्भीरता एवं सतर्कता नहीं बरती गयी जिससे मस्टर रौल के संधारण में त्रुटि के साथ-साथ अन्य अनियमितता हुई। निगरानी व्यूरो द्वारा भी उक्त आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०-९८/२००८, दिनांक 25.11.2008 दर्ज किया गया, जिसमें श्री चौबे के साथ-साथ अभियंतागण एवं पंचायत सचिव को भी अभियुक्त बनाया गया। इन्हीं आरोपों के क्रम में माननीय लोकायुक्त के स्तर पर भी मामला विचाराधीन है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री चौबे का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. अतएव काम के बदले अनाज योजना के कार्यान्वयन में अभिकर्ता को अग्रिम देने में लापरवाही बरतने एवं मस्टर रौल की जाँच तथा योजना के अनुश्रवण में समुचित सतर्कता नहीं बरतने के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 के तहत श्री सुधांशु कुमार चौबे, बिप्र०स०, कोटि क्रमांक-1089/08, 858/11 के विरुद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-

- (i) निन्दन (आरोप वर्ष-2005-06 के प्रभाव से)।
- (ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

6. निलंबन अवधि (दिनांक 09.02.09 से दिनांक 18.01.2010) के संबंध में निर्णय हेतु अलग से कार्रवाई करते हुए आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1016-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>